लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे दिसंबर 2022 तक होगा पूरा

राजधानी को नौ प्रोजेक्ट, डीआरडीओ केंद्र बनेगा, खुलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्टरी

अमर उजाला ब्यूरो

63 किमी लंबाई
छह लेन का बनेगा
4700
करोड़ का प्रोजेक्ट

- केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने दिया शहर को तोहफा
- डेडलाइन तय, जुलाई तक शिलान्यास की तैयारी

लखनऊ। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ-कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे (एनई-6) के निर्माण की डेडलाइन तय कर दी है। लखनऊ में शुक्रवार को टेढ़ी पुलिया फ्लाईओवर के लोकार्पण के दौरान गडकरी ने कहा कि 63 किमी लंबे और छह लेन के इस एक्सप्रेस-वे को एनएचएआई दिसंबर 2022 तक पूरा कर लेगा। यह एक्सप्रेस-वे कानपुर को लखनऊ एयरपोर्ट से जोड़ेगा।

गडकरी ने 4700 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट पर कहा कि जुलाई तक शिलान्यास कर इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। इससे कानपुर से लखनऊ का सफर 45 मिनट का रह जाएगा। जमीन अधिग्रहण का काम तेजी से पूरा हो रहा है। कानपुर के शुक्लागंज से शुरू होकर लखनऊ की आउटर रिंगरोड को कनेक्ट करते हुए यह एक्सप्रेस-वे शहीद पथ तक बनाया जाना है। इस दौरान, गडकरी ने शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के लिए नौ नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। वहीं, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने राजधानी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) का केंद्र खोलने की घोषणा की। इससे लखनऊ में ही रक्षा उद्योग से जुड़े उद्योगों के लिए शोध हो सकेगा।

डिफेंस कॉरिडोर से जुड़ेगा एनई-6

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि एनई-6 को डिफेंस कॉरिडोर का भाग बना दिया गया है। इससे लखनऊ-कानपुर के बीच उद्योगों के विकास करने में सहयोग मिलेगा। कई उद्यमी इसके लिए मंत्रालय के संपर्क में हैं।

टेढ़ी पुलिया फ्लाईओवर के लोकार्पण कार्यक्रम में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ।

अयोध्या में चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग बनेगा राष्ट्रीय राजमार्ग

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या में चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने की घोषणा की। इससे करीब 250 किमी लंबाई में परिक्रमा मार्ग के विकास और रखरखाव का खर्च केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय उठाएगा। परिक्रमा मार्ग के नवीनीकरण के काम का खर्च भी मंत्रालय उठाएगा। कार्यक्रम के दौरान ही रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने यह मांग रखी थी।

इलेक्ट्रिक वाहन के लिए 700 करोड़ का निवेश

राजनाथ सिंह ने बताया कि लखनऊ में आउटर रिंग रोड पर इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण इकाई लगेगी। इस प्रोजेक्ट पर दक्षिण कोरिया की कंपनी एडिशन मोटर्स व राजधानी का लधानी समूह 700 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। इस दौरान गडकरी ने कहा कि दो साल में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत डीजल वाहनों के बराबर हो जाएगी। ...माईसिटी पेज 3

यूपी में 3.5 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट

गडकरी ने बताया कि यूपी के विकास के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपये के नए प्रोजेक्ट शुरू कए जा रहे हैं। पहले यह लक्ष्य एक लाख करोड़ रुपये का था। यूपी का राज्यांश का सालाना बजट भी अब 11,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे सेतुओं और आरओबी के प्रोजेक्ट की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

योगी बोले- बेहतर हो रहीं सड़कें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि सड़कों के विकास को लेकर राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है। प्रदेश में राजमार्गों की संख्या बढ़ी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का काम 50 प्रतिशत पूरा हो गया है। मेरठ-प्रयागराज एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। किसी भी परियोजना के लिए हम सकारात्मक भूमिका में होंगे।

राजधानी से कानपुर तक रैपिड रेल चलाने की तैयारी

अमर उजाला ब्यूरो

फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराने के लिए केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव, केडीए को दी गई है परियोजना की प्रारंभिक तैयारी कराने की जिम्मेदारी

लखनऊ। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ की तर्ज पर लखनऊ-उन्नाव-कानपुर के बीच 'रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम' (आरआरटीएस) शुरू करने को लेकर मंथन शुरू हो गया है। आवास एवं नियोजन विभाग ने कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) को तीनों शहरों के बीच रैपिड रेल के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट (संभाव्यता) समेत अन्य तैयारियों को पूरा कराने की जिम्मेदारी दी है।

प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने बताया कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट केंद्र की ही किसी एजेंसी से तैयार कराया जाना है। जल्द ही इसका प्रस्ताव केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए सरकार इस रूट पर त्वरित गति वाली यातायात सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है। इस सिलसिले में आरआरटीएस परियोजना पर भी विचार किया जा रहा है। इससे लखनऊ से कानपुर के बीच सुगम व तीव्र यातायात की सुविधा मिल सकेगी।

2015 में भी तैयार हुआ था प्रस्ताव

अखिलेश सरकार ने 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए 2015 के अंत में दोनों शहरों के बीच आरआरटीएस शुरू करने का प्रस्ताव तैयार कराया था। मगर, प्रस्ताव केडीए के दफ्तर से बाहर नहीं निकल पाया। नई सरकार ने भी इस पर चर्चा शुरू की, लेकिन कानपुर में प्रस्तावित मेट्रो परियोजना को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था। अब कानपुर में मेट्रो परियोजना शुरू हो चुकी है। ऐसे में सरकार ने एक बार फिर आरआरटीएस शुरू करने को लेकर गंभीरता से पहल शुरू कर दी है।